सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

1-30 नवंबर, 2023 वर्ष-1 अंक-15/16, संयुक्तांक

निःशुल्क प्रति

अभेद्य होती भारतीय तटीय सीमाएं

सीमाओं की चाक-चौबंद सुरक्षा से ही देश सुरक्षित है

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

सीमाओं की चाक-चौबंद सुरक्षा से ही देश सुरक्षित है	12
सीमाओं एवं लोगों की सुरक्षा है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता	16
आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने का समय	22
हिमवीर शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ देश...	24
वंचितों का हित है मोदी सरकार की प्राथमिकता	26
अब कम होंगे सरकार में लंबित मामले	28
संकल्प से सिद्धि की सोच को जन-जन तक पहुंचा रहे ...	29
गेस्ट कॉलम	30

विशेष रिपोर्ट

05 अभेद्य होती भारतीय तटीय सीमाएं

10 तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण काम

20 सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियां खाद्य क्षेत्र...

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण था, जब प्रधानमंत्री ने दो साल पहले एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता के लिए भारत की पहल पर प्रकाश डाला था।

हमारे सुरक्षा बल और सेना के जवान लगातार देश की हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बीते नौ साल में समय और जरूरत के अनुसार हमने तटीय सुरक्षा तंत्र और निगरानी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

हाल ही में, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले प्रत्येक परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। हर भारतीय के लिए वह पल गर्व का क्षण था, जब प्रधानमंत्री महोदय ने दो वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने समुद्री व्यापार बढ़ाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत पांच सिद्धांत पेश किए थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। समुद्री विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर करने की बात कही। तीसरे सिद्धांत के रूप में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं व आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे। समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए। पांचवीं बात उन्होंने यह कही कि समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। पूरी दुनिया ने इन सिद्धांतों को गंभीरता से सुना और इस पर अमल करने की बात कही।

यूं तो भारतीय नौसेना समग्र रूप से समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी और सक्षम है, जिसमें तटीय एवं अन्य सुरक्षा शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय तटीय क्षेत्रों में निगरानी को बढ़ाने एवं गहन समुद्री गश्त के लिए नौ तटीय राज्यों एवं चार केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुपूरक तटीय सुरक्षा योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी लगातार तटीय सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश देते रहे हैं। अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में उन्होंने गुजरात के कच्छ जिले में संवेदनशील सर क्रीक और हरामी नाला का स्वयं दौरा किया और 257 करोड़ रुपये की लागत वाले 'मूरिंग प्लेस' की नींव रखी। इससे पहले 20 मई, 2023 को उन्होंने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी।

समुद्री तटीय सुरक्षा के साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल सहित अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरी तरह से अपने कर्तव्य निर्वहन में समर्पित हैं। 'सजग भारत' का यह संयुक्तांक आपके हाथों में है। हमारा मानना है कि आपके साथ के बिना यह यात्रा जारी नहीं रह सकती। इसलिए अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें। हमारा ई मेल है–sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

भारत की महिलाओं में हर क्षेत्र में लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। आज एक लाख से ज्यादा माताओं और बहनों को जो सीड कैपिटल दी गई है, उससे उनके उद्यम को काफी बढ़ावा मिलेगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारी बर्फबारी के कारण जिन सीमा चौकी पोस्ट पर पहले जरूरत की चीजें पहुंचाना मुश्किल था, वहां अब मोदी सरकार ड्रोन के माध्यम से दवाइयां, सब्जियां व जीवन रक्षक चीजें पहुंचाएगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है... माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक कल्याण के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Many congratulations to @BSF_India's mountaineering expedition contingent for the successful accomplishment of scaling Mt. Manaslu, eighth highest peak in the world. It's a matter of pride that two women personnel were also part of the team. My best wishes for future expeditions.

Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs

अधिक से अधिक भारतीय उत्पाद खरीदें और #VocalForLocal अभियान से जुड़ें। #NaMoApp पर अपने द्वारा खरीदे गए स्वदेशी उत्पादों या उन्हें बनाने वाले शिल्पकारों के साथ सेल्फी पोस्ट करें। अपने प्रियजनों को भी इस सेल्फी थ्रेड से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

भारत की 140 करोड़ जनता वीर जवानों के त्याग, बलिदान, साहस और शौर्य का पूरे दिल से सम्मान करती है ।ITBP के हिमवीरों ने शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ भारत की दुर्गम सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

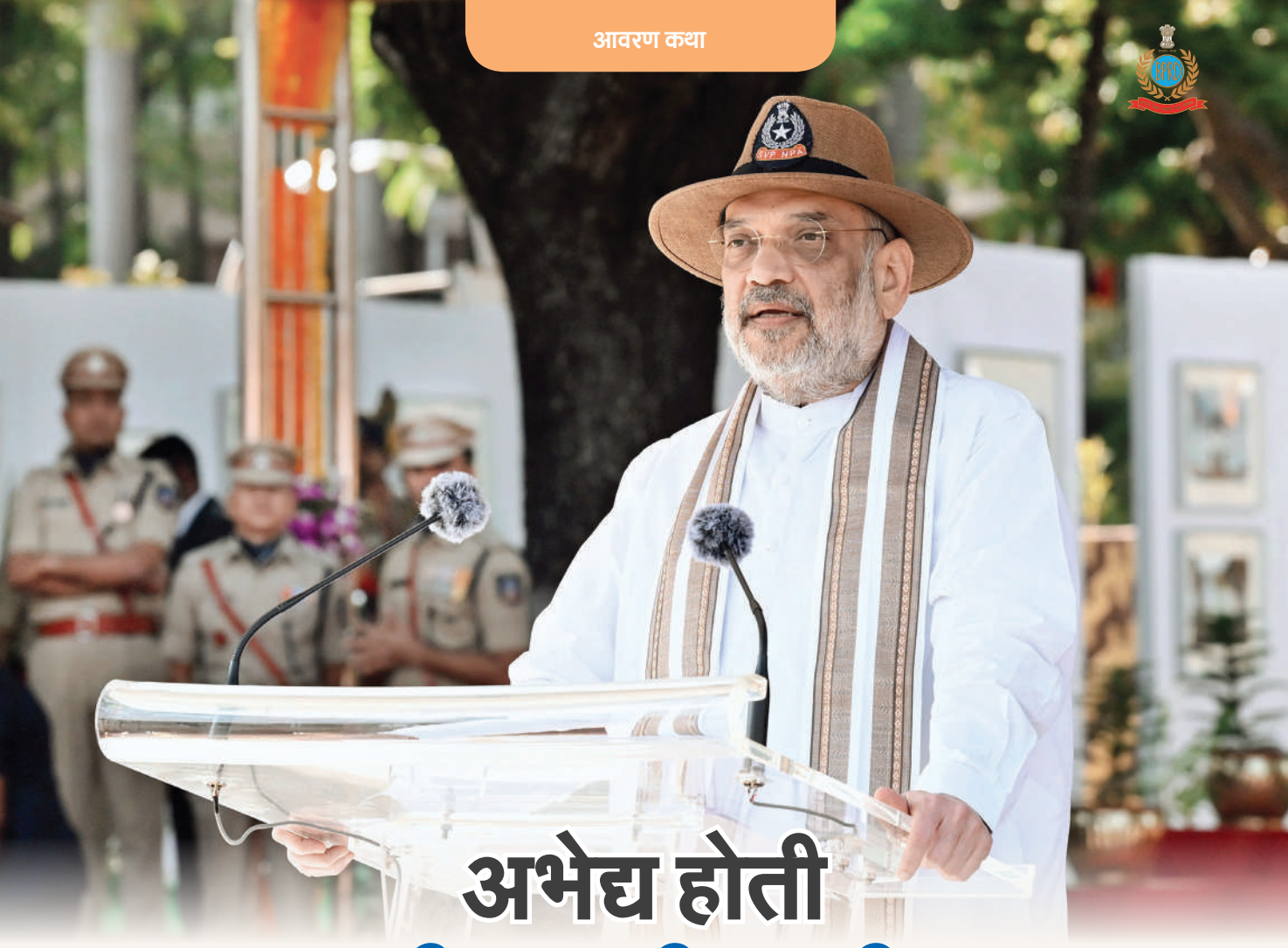

अभेद्य होती भारतीय तटीय सीमाएं

तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण काम मोदी सरकार की दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय के कारण हो रहा है

ब्यूरो

भारत के हजारों किलोमीटर लंबी तटीय इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाओं को अमल में लाती है। स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह तटीय इलाकों का दौरा करते हैं और वहां सुरक्षा बलों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाते हैं। सुविधाओं और सुरक्षा के तंत्रों को आधुनिकतम बनाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने की

> केंद्र सरकार समुद्री खतरों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा की चुनौतियों का गंभीरता से आंकलन कर रही है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तटीय सुरक्षा को मजबूत और अभेद्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च, 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन राष्ट्र को समर्पित किया और इसके पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की। साथ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रहे।

हमारा हजारों किलोमीटर का तटीय क्षेत्र सामरिक और व्यापारिक रूप से बेहद अहम है। समुद्री सीमा की सुरक्षा में जहां भारतीय नौसेना अपने शौर्य का परिचय देती आ रही है, तो इसके तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटीय सुरक्षा पुलिस बल के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय निभा रहा है। सुरक्षा से जुड़े लोगों को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए सरकार अकादमी बनाकर हजारों लोगों को प्रशिक्षित करेगी। बीते नौ वर्षों में तटीय सुरक्षा अभेद्य हो चुकी है।

दिशा में काम कर रहा है। सभी हितधारकों के सुझावों के साथ इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि गृह मंत्रालय तटीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों का गंभीरता से आंकलन कर रहा है। तटीय सुरक्षा में कई मंत्रालयों और एजेंसियों की भूमिका होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हितधारकों के साथ बैठक के बाद उनके बीच आपसी समन्वय स्थापित करके इसे और मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मियों और मछुआरों के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी चर्चा की जगई। समुद्र में जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बीच टकराव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी चर्चा की गई। समुद्र तट की सुरक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तट के किनारे परमाणु स्टेशन, मिसाइल-प्रक्षेपण केंद्र, रक्षा और तेल प्रतिष्ठान हैं। पूरे देश में कुल तटीय पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 12 हजार है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती अलग-अलग क्षेत्रों में की गई है।

भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कनार्टक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल सहित दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत के तट सदैव अपराधियों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में माल, सोना, नशीले पदार्थों, विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के साथ-साथ इन तटों के माध्यम से देश में आतंकवादियों की घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं। पुरानी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए हैं।

सुरक्षा का सुदर्शन चक्र

देश में कुछ समय पहले तक तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की कोई नीति नहीं थी। हजारों किलोमीटर तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पास थी और भारतीय सेना की भागीदारी भी इसमें अहम थी। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को मंजूरी दी। इसके बाद गुजरात के द्वारका में अकादमी बनाने का निर्णय हुआ। लक्ष्य रखा गया है कि हर वर्ष करीब तीन हजार लोगों को यहां प्रशिक्षित किया जाएगा। अब समुद्र के तटीय इलाकों की सुरक्षा

20 मई 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (एनएसीपी) के परिसर की आधारशिला रखी।

का कार्य पहले से अधिक पेशेवर तरीके से किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के अनुसार, सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम्स और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का एक सुदर्शन चक्र बनाया है। समेकित विचार के साथ बनाई गई इस रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है। खुले समंदर में भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों द्वारा सुरक्षा की जाती है।

मध्यस्तरीय समुद्र में भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल सुरक्षा और प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर) में सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग इसे अंजाम देती है और गांव में देशभक्त मछुआरे सूचना का माध्यम बनकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इन सभी आयामों पर भारत सरकार ने एक सुगठित तटीय सुरक्षा नीति अपनाई है और एक समेकित विचार के साथ बनाई गई नीति और रणनीति के माध्यम से देश के तटों को सुरक्षित करने का काम किया है।

कोई अब नहीं दिखा सकता है आंख

देश ने तटीय सुरक्षा में कोताही के कारण कई दुष्परिणाम भोगे हैं। 2008 मुंबई हमले को कोई नागरिक भुला नहीं सकता, जिसमें थोड़ी सी चूक के कारण 166 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। सरकार की तटीय सुरक्षा की नीति के बाद अगर दुश्मन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा, तो उसे यहां से दांत खट्टे करने वाला जवाब मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि कई स्तंभों पर तटीय सुरक्षा की नीति को तैयार किया गया है। इसमें तटीय सुरक्षा और इंटेलीजेंस के मामले में समन्वय और संवाद, संयुक्त तटीय गश्त द्वारा पेट्रोलिंग के प्रोटोकॉल तय करके निश्चित समय अंतराल पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, 10 लाख से ज्यादा क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड मछुआरों को देना, 1537 फिशलीडिंग पॉइंट्स पर सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करना और ब्लू इकोनामी के लिए बनाए हुए सभी मत्स्य बंदरगाहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

हजारों किलोमीटर लंबा है भारत का समुद्री तट

भारत की 15000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। श्री शाह ने कहा कि 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा में से 5422 किलोमीटर मेनलैंड की सीमा है और द्वीपों की 2000 किलोमीटर की सीमा है। इस 7516 किलोमीटर की समुद्री सीमा पर कुल मिलाकर समुद्र किनारे 1382 द्वीप समूह, 3337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर-प्रमुख बंदरगाह, स्पेस, डिफेंस, अटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, शिपिंग आदि 135 एस्टेबलिशमेंट हैं। दरअसल, 2008 में मुंबई में 26/11 के हमले के बाद, सरकार द्वारा पूरे तट पर तटीय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई थी। सभी संबंधित पक्षों के समन्वित प्रयासों से, ये सभी उपाय अब लागू हो गए हैं और समग्र समुद्री सुरक्षा पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। भारतीय नौसेना इस संबंध में अग्रणी एजेंसी रही है और इस कार्य में भारतीय तट रक्षक, समुद्री पुलिस और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। नौसेना द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में तटीय सुरक्षा के लिए कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में स्थापित संयुक्त संचालन केंद्र (जेओसी) पूरी तरह से चालू हैं। इन जेओसी को भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक और समुद्री पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 24X7

संचालित किया जाता है।

एकल केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ सभी मछुआरों को आईडी कार्ड जारी करना, हमारे तट से संचालित होने वाली 2 लाख से अधिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पंजीकरण और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को उपयुक्त उपकरणों से लैस करना तथा पोत की पहचान और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम हैं। हमारे मछली पकड़ने वाले समुदाय कुशल नाविक हैं, जिनका सहयोग हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। मछुआरा समुदाय हमारी सुरक्षा वास्तुकला की 'आंख और कान' बन गए हैं। यह देश के सभी तटीय जिलों में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संचालित तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन समुदायों में जागरूकता फैलाकर हासिल किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान में अकेले 2014 में लगभग 70 ऐसे अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के दौरान मछुआरों को दृढ़ता से सलाह और चेतावनी दी गई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार न करें क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के हित में है। मछुआरों के पास आज जीपीएस रिसीवर हैं और इसलिए वे समुद्र में अपनी स्थिति से पूरी तरह अवगत रहते हैं। नौसेना और तटरक्षक बल ने सभी तटीय राज्यों में समुद्री पुलिस को समय-समय पर समुद्री प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। डब्ल्यूएनसी में ही 2014 में 250 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। स्थायी पुलिस प्रशिक्षण सुविधा के लिए तमिलनाडु और गुजरात में समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को हाल ही में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। ये समुद्री पुलिस को पेशेवर प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहे हैं।

सुमुद्री तट पर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई हैं और सीमाओं और देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पिछली सरकार के 10 साल के शासनकाल में कुल ₹680 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए लेकिन अब एक ही खेप में ₹12

तटीय सुरक्षा का सशक्तिकरण

हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किया है, जो ये बताता है कि हमारी एजेंसियां और अधिक मुस्तैद हुई हैं।

'ऑपरेशन सजग' ने दिखाई तैयारी और ताकत

सितंबर, 2023 के तीसरे सप्ताह में भारतीय तटरक्षक द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट पर 'ऑपरेशन सजग' किया गया। तटरक्षक दल के इस विशेष अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने हिस्सा लिया। 'ऑपरेशन सजग' तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। तटरक्षक दल के मुताबिक, यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुर्नमूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। इस अभ्यास के दौरान, समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं, नावों और छोटे जहाजों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किये गए पास की व्यापक जांच एवं सत्यापन किया गया। सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना ने भी इस अभ्यास में शिरकत की।

अभ्यास में तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य के साथ मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग, मछली उतारने वाले केंद्रों की व्यवस्था और प्रवेश व निकास जांच बिंदुओं पर पूर्ण नियंत्रण व तटीय मानचित्रण जैसे कई उपाय शामिल किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं। नौकाओं की निगरानी के अलावा, तटीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत द्वीपों की सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों को संस्थागत बनाया गया है। तटरक्षक दल के मुताबिक, तटीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर महीने एक दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है। दल का कहना है कि इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यह अभ्यास महत्वपूर्ण प्रशिक्षण परिणाम को सामने लाने और तटीय सुरक्षा में प्राप्त हुए रुझानों को प्रस्तुत करने के अलावा विभिन्न तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। ■

नौ साल में तटीय सुरक्षा का सशक्तिकरण

तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारू क्रियान्वयन

- तटीय प्रदेशों में 120 तटीय पुलिस स्टेशन, 06 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर, 37 जेटी, 131 चार पहिया वाहन और 242 दोपहिया वाहन प्रदान किए गए।

तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय

- तटीय सुरक्षा और आसूचना के समन्वय पर पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित की गई।
- भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पड़ोसी समुद्री देशों में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय।

संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल तय किए गए

- अगस्त 2020 से प्रभावित ढंग से शुरू किया गया।
- तटीय जल तथा तटीय रेखा को प्रभावकारी रुप से सुरक्षित रखने के लिए नया तटीय पेट्रोलिंग/ एसओपी/पैटर्न/ प्रोटोकॉल लाया गया। 30 जून 2023 तक 1712 उड़ानें (sorties) और 1111 क्लास रूम निर्देश जिनमें 4115 कोस्टल पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (NACP)

- द्वारका, गुजरात स्थित राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी में 870 तटीय पुलिस/सीमा शुल्क कर्मियों ने समुद्री पुलिस फाउंडेशन कोर्स को पूरा किया।

मछुआरों की सुरक्षा

- मछुआरों की पहचान के लिए क्यूआर कोड सक्षम पीवीसी आधार कार्ड का प्रावधान कर सुरक्षा के प्रयासों को और सक्षम बनाया गया।
- लगभग 12 लाख क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड वितरित।
- 3 लाख से अधिक नौकाओं का पंजीकरण।
- सितंबर, 2020 में मछली पकड़ने की नौकाओं की कलर कोडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
- 1537 मत्स्य अवतरण बिन्दुओं को चिन्हित कर सर्वेक्षण करना।
- मछुआरों के लिए राष्ट्रव्यापी टोल फ्री नम्बर 1554।
- सिंगल प्वाइंट मूरिंग्स (एसपीएम) की सुरक्षा पर एसओपी निश्चित।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, कस्टम्स और मछुआरों के साथ मिलकर सुरक्षा का

एक सुदर्शन चक्र बनाया है

हजारों किलोमीटर समुद्री तट की सुरक्षा को लिए विशेषज्ञों को तैयार करने का जिम्मा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के पास है। 20 मई, 2023 को जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। आधुनिक तकनीक से 470 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है।

ब्यूरो

राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी पहली राष्ट्रीय अकादमी है, जो समुद्री पुलिस कर्मियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह नौ तटीय राज्यों, पांच केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करती है। अकादमी समुद्री पुलिस की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया जा सकता है।

20 मई, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी । अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। अकादमी का उद्देश्य सालाना तीन हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस का उद्देश्य देश भर में तटीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। अकादमी समुद्री पुलिस कर्मियों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें संभावित खतरों से भारत की विशाल तटरेखा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने

> **मोदी सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर देश की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

में सक्षम बनाया जा सकता है। अकादमी के प्रयास राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, तस्करी, समुद्री डकैती और अनधिकृत मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने और तटीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तटीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 450 एकड़ से अधिक भूमि पर राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी का काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश और देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है और देश के नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे सीमा प्रहरियों के रहने और काम करने की सुविधाओं में सुधार हो, उन्हें अत्याधुनिक उपकरण मिलें और वे अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमारे सुरक्षा बलों को हर तरह की सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो विकास का कोई मतलब नहीं है। कोई भी देश अपनी सीमाओं की अचूक सुरक्षा से ही सुरक्षित रह सकता है। भारत की 15,000 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा और 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। उन्होंने कहा कि 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा में से 5,422 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा है और 2,000 किलोमीटर से अधिक द्वीपों की सीमा है। यहां 1,382 द्वीप, 3,337 तटीय गांव, 11 प्रमुख बंदरगाह, 241 गैर-प्रमुख बंदरगाह और अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, शिपिंग आदि सहित 135 प्रतिष्ठान हैं। पहले इन सभी के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण प्रणाली नहीं थी। लेकिन 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद, प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन, सीमा सुरक्षा और तटरक्षक बल के जवानों से सुसंगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता महसूस की गई।

श्री शाह ने कहा कि यह तभी संभव है जब तटीय सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये . उन्होंने कहा कि 2018 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को मंजूरी दी और इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि द्वारका का अर्थ है देश का प्रवेश द्वार और उस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा से इस स्थान पर आए थे और हमारी समुद्री सीमा के पार एक बड़ा व्यापार केंद्र बनाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल्पना से पूरे देश की तटीय सुरक्षा का प्रशिक्षण भगवान श्रीकृष्ण की भूमि ओखा में दिया जा रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में तटीय पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 12,000 है और एक बार जब यह अकादमी पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो एक वर्ष में 3,000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इस तरह 4 साल के अंदर भारत की तटीय सुरक्षा में लगे सभी जवानों की 100 फीसदी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के कारण आज तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास है और अपने खून की आखिरी बूंद बहने तक बीएसएफ के जवानों ने देश की एक-एक इंच जमीन के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। सीमा सुरक्षा बल की ये वीरगाथा देश का बच्चा-बच्चा जानता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तटीय सुरक्षा नीति कई स्तंभों पर आधारित है। इसमें तटीय सुरक्षा और खुफिया मामलों में समन्वय और संचार, निश्चित समय अंतराल पर गश्त के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करके संयुक्त तटीय गश्त, मछुआरों की सुरक्षा, मछुआरों को क्यूआर कोड के साथ 10 लाख से अधिक आधार कार्ड देना, 1537 मछलियों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बनाए गए सभी मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर प्रमुख बिंदु और सुरक्षा। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों को जोड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए एक अभेद्य किला स्थापित किया गया है।■

विशेष बातें

- **केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के ओखा में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है।**
- **राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी , देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी, नौ तटीय राज्यों, पांच केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस बलों की समुद्री पुलिस को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2018 में स्थापित की गई थी।**
- **अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य तटीय पुलिस कर्मियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है।**
- **भारत सरकार ने आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एनएसीपी को विकसित करने के लिए 441 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं., जिससे तटीय सीमा सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।**

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सीमाओं की चाक-चौबंद सुरक्षा

समय और जरूरत के हिसाब से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां खुद को अपडेट करती हैं। जैसे ही सूचना तस्करों की सूचना मिलती है, सीमा पर दबिश दी जाती है। देश की हजारों किलोमीटर लंबी तट की सुरक्षा करने वाली एजेंसियां एक के बाद नए मुकाम हासिल कर रही है।

ब्यूरो

जब हम तटीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें न केवल बाहरी खतरों से सुरक्षा शामिल है, बल्कि इसमें समुद्र तटों पर लोगों की सुरक्षा भी शामिल है। हमारी हजारों किलोमीटर लंबी तटीय क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ संबंधित राज्य पुलिस बलों के आपसी समन्वय और सहयोग से लगातार अपडेट होती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले की लगातार निगरानी भी करता रहता है। गृह मंत्रालय की सजगता का ही परिणाम है कि कई राज्य आज तटीय सुरक्षा को लेकर चौकस हो गए हैं।

रास्ता दिखाता है गोवा

गोवा राज्य, अपनी 105 किलोमीटर लंबी तटरेखा और प्रसिद्ध समुद्र तटों के साथ, बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद, तटीय सुरक्षा यहां की प्राथमिकता बन गई। गोवा तटीय सुरक्षा पुलिस ने गृह मंत्रालय से इंटरसेप्टर नौकाओं और आरआईबी से सुसज्जित सात स्टेशन स्थापित किए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने साल भर समुद्री निगरानी के लिए एक ऑल-वेदर वेसल प्रदान किया। तटीय सुरक्षा पुलिस ने इन क्षेत्रों की निगरानी करने और

से ही देश सुरक्षित है

मछली पकड़ने वाले जहाजों और चालक दल के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए ड्रोन के उपयोग सहित निगरानी उपाय शुरू किए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है। तैयारियों को बनाए रखने के लिए कर्मियों का नियमित प्रशिक्षण, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना के साथ संयुक्त गश्त और अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं।

मेथमफेटामाइन की जब्ती

जिन क्षेत्रों में पुलिस की चिंता है, वहां केवल इनपुट ही पर्याप्त नहीं है। इनपुट तभी प्रभावी होते हैं, जब उन पर कार्रवाई की जाती है। 3 मार्च की रात को गुजरात एटीएस को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास एक ईरानी नाव द्वारा नशीले पदार्थों की संदिग्ध तस्करी के बारे में एक खुफिया इनपुट मिला। भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) द्वारा एक व्यापक खोज अभियान के बाद एक रडार संपर्क का पता चला जो आईएमबीएल को पार कर भारतीय जल सीमा की ओर बढ़ रहा था। आईसीजी जहाजों ने तुरंत लक्ष्य का पीछा किया। जैसे ही आईसीजी जहाज करीब आया, संदिग्ध जहाज ने भागने का प्रयास करते हुए टालमटोल करना शुरू कर दिया। कुछ देर पीछा करने के बाद नाव को पकड़ लिया गया। तलाशी दल ने पांच संदिग्ध बोरियों को बरामद किया, जिनमें एक कार्यात्मक थुरया सैटेलाइट फोन के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में ₹425 करोड़ मूल्य के मेथामफेटामाइन के 61 सीलबंद पैकेट थे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के सामने समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया था प्रधानमंत्री ने

9 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत पांच सिद्धांत पेश किए। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। पहले सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। वैश्विक समृद्धि समुद्री व्यापार के सहज संचालन पर निर्भर करती है। समुद्री व्यापार के समक्ष कोई भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकती है। दूसरे सिद्धांत को लेकर उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरे सिद्धांत के बारे में कहा कि वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण और समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना, प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए चौथे और पांचवें सिद्धांत रहे।परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। परिचर्चा, समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समुद्री क्षेत्र में समन्वय मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित थी। हालांकि, यह पहली बार था जब उच्च स्तरीय खुली बहस में एक विशेष एजेंडे के रूप में समुद्री सुरक्षा पर समग्र रूप से चर्चा की गई।

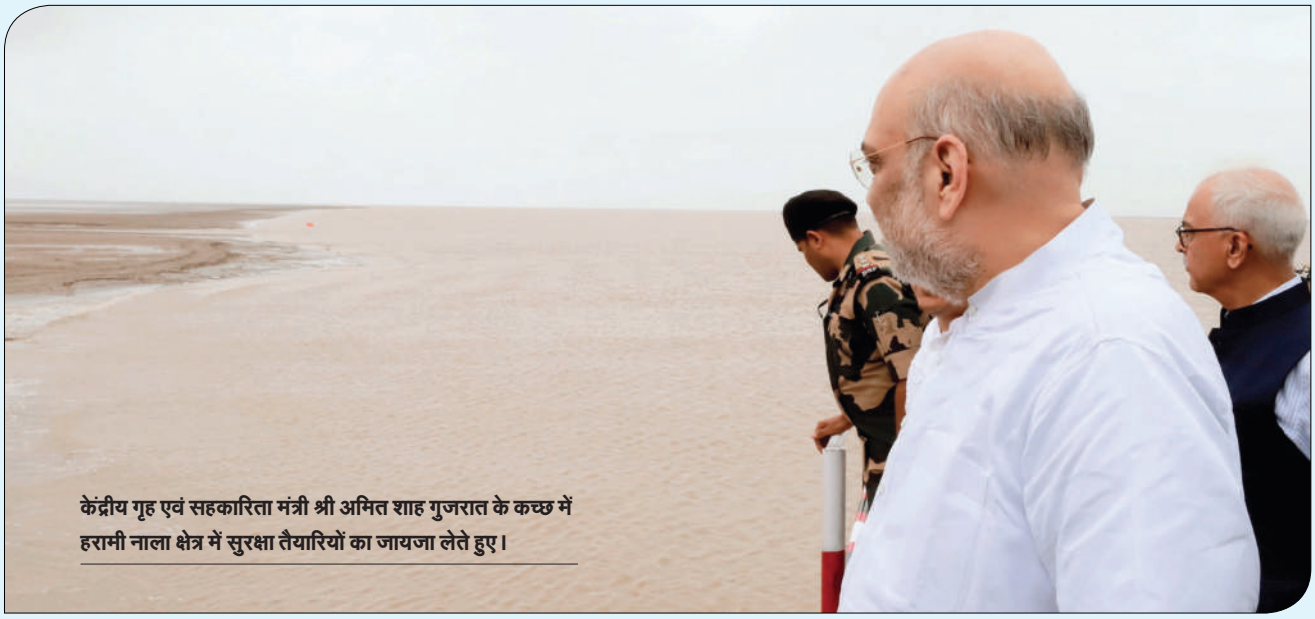

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह गुजरात के कच्छ में हरामी नाला क्षेत्र में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते हुए।

डीजल तस्करी

17 मई को, मुंबई के तट पर नियमित मासिक तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सजग' के हिस्से के रूप में, भारतीय तट रक्षक जहाज (आईसीजीएस) समुद्र प्रहरी ने भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव (आईएफबी) 'द्वारकाधीश' पर एक बोर्डिंग ऑपरेशन चलाया। स्थानीय खुफिया जानकारी द्वारा निर्देशित ऑपरेशन में जहाज पर 11 टैंकों में संग्रहीत लगभग 15 किलोलीटर डीजल बरामद किया गया।

सोना जब्त कर लिया गया

भारतीय तटरक्षक स्टेशन मंडपम और राजस्व खुफिया निदेशालय टीम के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास में, 30 मई से 1 जून तक एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत, एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव 'ब्लैक पर्ल' और इसके तीन चालक दल के सदस्यों को तमिलनाडु तट से पकड़ लिया गया। चालक दल ने सोने की खेप फेंककर कब्जे से बचने का प्रयास किया, आईसीजी ने गोताखोरी अभियान के साथ तेजी से जवाब दिया और पानी से 32 .869 किलोग्राम कीमती धातु बरामद की। बरामद सोने का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹20 .21 करोड़ था।

समुद्री खीरे की जब्ती

1 अगस्त को, भारतीय तटरक्षक स्टेशन (आईसीजीएस) मंडपम ने संभावित प्रतिबंधित सामग्री स्थानांतरण के संबंध में खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के लिए तुरंत एक निगरानी टीम तैनात की गई और तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में उचिपुली समुद्री तट क्षेत्र के पास मिशन का समर्थन करने के लिए एक आईसीजी मंडपम रिजिड इन्फ्लैटेबल बोट (आरआईबी) को पुनर्निर्देशित किया गया।

निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने पर, टीम को मंडपम के उत्तर में स्थित उचिपुली

महत्वपूर्ण पहल

- महत्वपूर्ण संपत्तियों और बिन्दुओं का तटीय मानचित्र समूचे भारत के लिए
- गैर-प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी
- ईईजेड तक अपराध की जांच के लिए 10 तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना
- तटीय सुरक्षा के लिए समर्पित कैडर का निर्माण किया जा रहा है
- एक समान तटीय सुरक्षा संगठनात्मक संरचना/ क्षेत्राधिकार निश्चित करना
- रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार तटीय समुद्र और तटीय रेखा की प्रभावी सुरक्षा, आईसीजी और तटीय पुलिस के बीच वास्तविक समय में समन्वय के लिए आईसीजी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है
- फिश लैंडिंग सेंटरों की निगरानी के लिए तकनीकी समाधान ढूंढना
- सभी तटीय राज्यों में समुद्री बोर्डों का गठन किया गया केवल ओडिशा में समुद्री बोर्ड का गठन शेष है
- घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरएस) में समुद्री घटनाओं की रिपोर्टिंग के प्रावधान को शामिल किया गया
- बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of port security-BoPs) के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ
- सामान्य संचार योजना: COMPLAN 2022 की घोषणा अब चरणबद्ध तरीके से COMPLAN 2022 का क्रियान्वयन प्रगतिशील है

तट पर समुद्री खीरे से भरी छह बोरियां मिलीं। आईसीजी टीम ने समुद्री खीरे को जब्त कर लिया और बाद में इसे आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया। जब्त किए गए समुद्री जानवरों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹57 .17 लाख है।

सुपारी जब्त

14 अगस्त को तटरक्षक जिला मुख्यालय-8 को पश्चिम बंगाल के बृंदाबनचक के पास तस्करी गतिविधियों में एक मछली पकड़ने वाली नाव की संदिग्ध संलिप्तता के बारे में खुफिया जानकारी मिली। जवाब में 15 अगस्त को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स), राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। ऑपरेशन में बृंदाबनचक के पास सनराइज प्वाइंट बीच पर इंडियन फिशिंग बोट (आईएफबी) की पहचान की गई। मौके पर पहुंचने पर, टीम को जहाज के भीतर सुपारी के 590 बैग मिले। जब्त की गई खेप का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹309 .76 लाख था।

तमिलनाडु पुलिस के तटीय सुरक्षा समूह ने प्रतिष्ठित समुद्र तट पर लगातार डूबने की घटनाओं के निराकरण के लिए चेन्नई में मरीना बीच लाइफगार्ड यूनिट शुरू करके एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। तमिलनाडु पुलिस को मरीना बीच पर डूबने की बड़ी संख्या में घटनाओं का सामना करना पड़ा था, जो एक वर्ष में औसतन लगभग 66 थी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने तटीय सुरक्षा समूह को इन घटनाओं को कम करने का काम सौंपा, जिसके कारण प्रशिक्षित लाइफगार्ड, जीवन रक्षक उपकरण और एआई-संचालित ड्रोन जैसे तकनीकी समाधानों के साथ मरीना बीच लाइफगार्ड यूनिट की शुरूआत हुई, जिससे समुद्र तट पर गतिशीलता को बढ़ावा मिला। साथ ही स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदाय से लाइफगार्ड की भर्ती करते हुए, समुद्र तट पर गतिशीलता के

लिए गैर-पारंपरिक वाहनों का परीक्षण और उपयोग आरंभ किया गया और तमिलनाडु मानवरहित हवाई वाहन निगम लिमिटेड के सहयोग से एक विशेष लाइफगार्ड ड्रोन विकसित किया गया। यह ड्रोन, जो भारत में पहला है, पेलोड ले जा सकता है और तेज हवाओं में काम कर सकता है। इससे पांच किलोमीटर के दायरे में त्वरित बचाव में सहायता मिलती है। 1 अप्रैल, 2022 को अपनी स्थापना के बाद से यूनिट ने 20 सितंबर, 2023 तक 97 लोगों की जान बचाई है। इसने स्थानीय मछुआरों को नियमित आय भी प्रदान की है और तटीय सुरक्षा को बढ़ाते हुए समुदाय के साथ मजबूत रिश्ते को बढ़ावा दिया है। इस पहल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने के एक थिंक टैंक, स्कॉच (SKOCH) की ओर से गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में एक सफल नवाचार के रूप में मान्यता दी गई। ■

तटीय सुरक्षा की आँख और कान

यदि स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होगा, तो आपराधिक एवं अवैध गतिविधियों को रोकने में सफलता नहीं मिल सकती है। वे समुद्र में सूचना और सतर्कता के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक हैं। भारतीय तटरक्षक की रणनीति स्थानीय लोगों को तटीय सुरक्षा तंत्र की आंख और कान के रूप में विकसित करना है। इस रणनीति में मछली पकड़ने वाले समुदाय के साथ जुड़ना और उसका समर्थन करना भी शामिल है। इस दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों (सीआईपी) की एक श्रृंखला शुरू की गई है। ये कार्यक्रम मछुआरों को उनकी समुद्री यात्राओं के दौरान जीवनरक्षक गियर ले जाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसके अतिरिक्त मछुआरों को आवश्यकता पड़ने पर भारतीय तट रक्षकों से संपर्क करने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसपोंडर (डीएटी) के उपयोग और अन्य आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। मछली पकड़ने वाले समुदाय को 24x7 खोज और बचाव (एसएआर) हेल्पलाइन 1554 के बारे में भी अवगत कराया गया, जो समुद्र में एसएआर सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर है। लाइफ जैकेट के उचित उपयोग, डीएटी के संचालन और सिग्नल फ्लेयर अग्निशामक यंत्रों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावहारिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। सुरक्षा जागरूकता को और बढ़ाने के लिए, मछली पकड़ने वाले समुदाय के बीच जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाले पर्चे वितरित किए गए।

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सीमाओं एवं लोगों की सुरक्षा है

अगले 2 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी सीमा को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सीमा सुरक्षा नीति बहुत स्पष्ट और सटीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और सीमावर्ती गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही इन गांवों में कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जा रहा है।

ब्यूरो

बीते दशक में सरकार ने देश को चार मजबूत स्तंभ दिए हैं, जो हैं सम्मान, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, वंचितों का कल्याण और बुनियादी ढांचे का विकास। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल पूरे दमखम के साथ तैनात हैं, वहीं नेपाल-भूटान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल निगहबानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सीमाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा और देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। सरकार देश को हर तरह के खतरों से सुरक्षित रखने और विकास की राह पर अभूतपूर्व गति से आगे रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का सूत्र वाक्य दिया है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई काम हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता सशस्त्र बलों को मजबूत कर रही है और उन्हें हर तरह की चुनौतियों से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए नवीनतम हथियारों/ उपकरणों से लैस कर रही है। कुछ समय पहले सीमा सुरक्षा बल के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और ये तभी संभव है जब हमारे वीर जवानों के त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वीर जवान देश के विकास की नींव हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों का जीवन सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ देश के युवाओं को अनुशासन का संदेश भी देता है।

उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद देश की सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला सीमा सुरक्षा बल भारत के पांच केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। वर्तमान में 186 बटालियन और 2.57 लाख कर्मियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

एक दिसंबर को हर वर्ष सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2023 में झारखंड के हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह पधारे थे। देश की सीमाई सुरक्षा और सुरक्षा बलों के अवदान की बात करते हुए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल की तैनाती। इस निर्णय के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश की सबसे दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल को मिली, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने बखूबी निभाया है। साथ ही यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाके, पूर्वोत्तर के पहाड़, गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान हों, गुजरात का दलदली इलाका हो या फिर सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल हों, सीमा सुरक्षा बल ने हमेशा मुस्तैद रहते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को विफल किया है। सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा और वीरता के नए मानक स्थापित किए हैं। श्री शाह ने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होतीं, वो देश कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में सीमाओं पर लगभग 560 किलोमीटर बाड़ लगाकर घुसपैठ और स्मगलिंग पर लगाम कसने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी सीमा को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर लिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सीमा पर 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लडलाइट्स लगाई गई हैं, 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 510 ऑब्जरवेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं, पहली बार हरामी नाला क्षेत्र में ऑब्जरवेशन टावर बनाए गए हैं, 637 आउटपोस्ट पर बिजली और

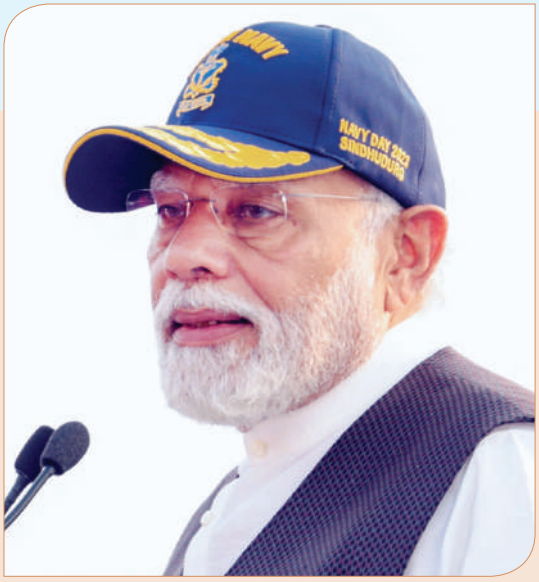

हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है, सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हैं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

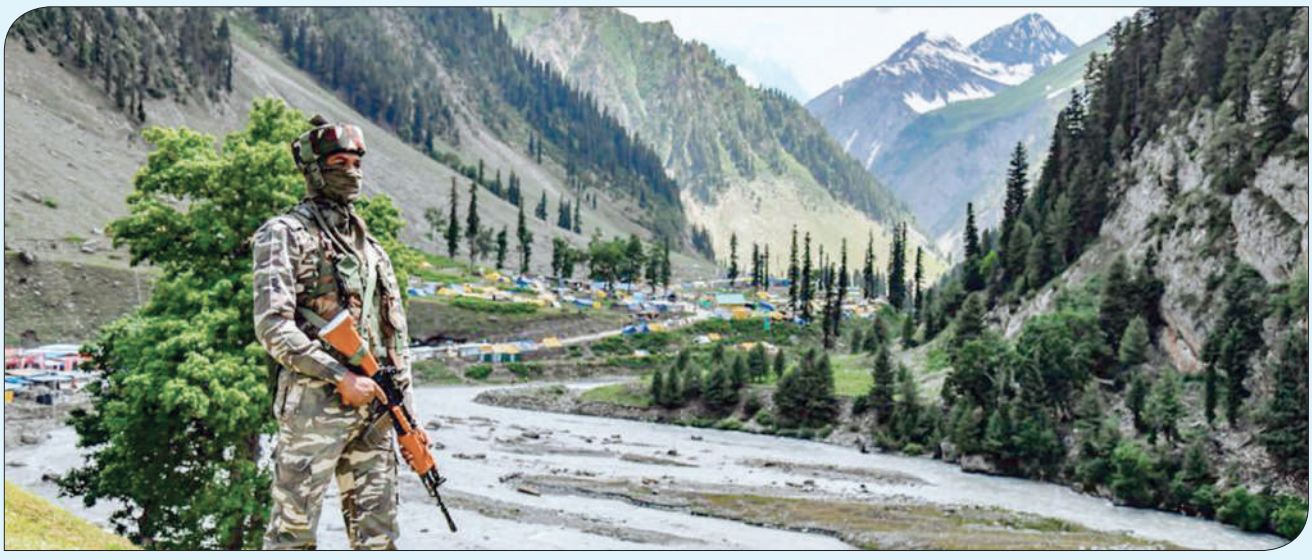

लगभग 500 स्थानों पर पानी कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा 472 जगह पर सोलर प्लांट लगाकर सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को सुनिश्चित किया गया है।

समय और जरूरत के अनुसार आधुनिक तकनीक से लैस होकर सुरक्षा बल के जवान भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बकौल श्री अमित शाह, सीमा सुरक्षा बल ने 2500 से ज्यादा हथियार पकड़े हैं और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिकतम तकनीक के साथ सीमा सुरक्षा बल ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 90 से ज्यादा विदेशी ड्रोन मार गिराए हैं और इसके रूट की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल ड्रोन और साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित कर अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने एरिया डोमिनेशन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ 100 ड्रोन उपलब्ध कराए हैं, जिसका बहुत अच्छा उपयोग सीमा सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं।

दूसरे देशों से लगी सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही सीमावर्ती इलाकों का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में सीमावर्ती गांवों को केंद्र सरकार विशेष रूप से विकास की धारा से जोड़ना चाहती है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इसका बड़ा उदाहरण है। 23 मई, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में एक कार्यशाला की अध्यक्षता की थी। उस दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, गांवों को सुरक्षित रखे बिना हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। चिन्हित गांवों में गतिविधियां बढ़ाना, पलायन रोकना, नागरिक सुविधाएं

देश की सीमाओं की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में सीमा सुरक्षा बल ने जिस तरह से देश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की है, उससे पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के इन वीर जवानों पर गर्व करता है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

स्पष्ट नीति-सुरक्षित सीमा

- सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत आधारभूत संरचना के निर्माण को बल
- सीमा क्षेत्रों के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन
- सीमा क्षेत्रों के साथ रेलमार्ग, सड़क मार्ग, जलमार्ग का सुगम जुड़ाव
- भू-सीमा से व्यापार को बढ़ावा देना
- जनता से सीधा संवाद

प्रमुख नीतिगण निर्णय

- सीमा पर आधारभूत संरचना में तेजी: फेंसिंग, बॉर्डर रोड, फ्लडलाइट्स और सीमा चौकी का निर्माण
- सीमा क्षेत्र में गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित अधिकार घोषित
- सीमा क्षेत्र विकास: सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव, वाइब्रेंट विजेल प्रोग्राम तथा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रियान्वयन में तेजी
- सीमा व्यापार: एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी)

उपलब्ध करवाने जैसे काम किए जाने चाहिए और सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि देश की मुख्य भूमि से ज्यादा से ज्यादा नागरिक,विशेषकर युवा इन गांवों में पर्यटन के लिए आएं और देश की सीमाओं की परिस्थिति से अवगत हो,यह जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम केवल पर्यटन और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों का देश की सीमाओं के साथ भावनात्मक और एकात्मक जुड़ाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जोकि देश की सुरक्षा और एकता के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े विजन के तहत साल 2014 में पहले सीमाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की शुरुआत की, फिर ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाईं और अब वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिससे गांव से होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा।

गौर करने योग्य यह भी है कि 20 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 'प्रहरी' मोबाइल ऐप और 13 मैनुअल के संशोधित संस्करण का लोकार्पण किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह ऐप सक्रिय शासन का एक बड़ा उदाहरण है, अब जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्यमान-सीएपीएफ व अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जवान ऐप के जरिये यह सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा। इसके साथ ही 13 मैनुअल में प्रतीक्षित रिविजन तथा अपडेट से ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग की कार्यों की बेहतर समझ बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। इस दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति के कारण सीमा पर कुछ स्थानों पर फेंसिंग नहीं हो पाती थी, बीएसएफ ने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्विलांस के लिए इन-हाउस टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी कीमत बहुत कम है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर जहां सीमा सुरक्षा बल काम कर रही है, वहीं भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल सतर्क और सजग होकर निगहबानी में लगी हुई है। सीमा की निगहबानी के साथ भारत -नेपाल के मैत्री संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए यह सेतु का कार्य कर रही है। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की मुस्तैदी से ही तस्करी, घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा है। कुछ समय पहले सशस्त्र सीमा बल की 19 वीं बटालियन के मुख्यालय में सैनिक सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह

राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा था कि जिस तरह किसान अपने पसीने से खेत सींचता है उसी तरह बीते दो दशकों से हमारे जवान नेपाल और भूटान सीमा पर सीमा की निगहबानी के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्पित है।

उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सीमा बल को 1751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर एवं वर्ष 2004 में 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा पर देश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के जवान सीमा पर केवल सुरक्षा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सीमावर्ती ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। नेपाल सीमा पर बल की महिला जवान भी पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के कार्यों को अंजाम दे रही हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी यहां की एक बटालियन सीमा सुरक्षा में तैनात है। जहां पर एसएसबी के जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। जवान सीमा पर 24 घंटे पहरा रखते हुए अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए तत्पर हैं। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, अवैध घुसपैठ व अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा है। ■

सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियां खाद्य क्षेत्र को ले जा रही हैं नई ऊंचाइयों पर

ब्यूरो

भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तीव्र वृद्धि का कारण सरकार के निरंतर और समर्पित प्रयास रहे हैं। भारत में पहली बार कृषि-निर्यात नीति के निर्माण, राष्ट्रव्यापी लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास, जिले को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले 100 से अधिक जिला-स्तरीय केंद्रों के निर्माण, मेगा फूड पार्कों की संख्या में 2 से बढ़कर 20 से अधिक और भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। यह पिछले 9 वर्षों में 15 गुना वृद्धि को दर्शाती है। भारत से पहली बार निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादों में जैसे हिमाचल प्रदेश से काला लहसुन, जम्मू और कश्मीर से ड्रैगन फ्रूट, मध्य प्रदेश से सोया दूध पाउडर, लद्दाख से कार्किचू सेब, पंजाब से कैवेंडिश केले, जम्मू से गुच्ची मशरूम और कर्नाटक से कच्चा शहद शामिल हैं।

इसका जिक्र प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' के दूसरे संस्करण के उद्घाटन पर कहा। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए एक लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज के लिए आर्थिक सहायता का भी वितरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को 'दुनिया के खाद्य केंद्र' के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। वर्ल्ड फूड इंडिया के परिणाम भारत के

> **भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खान-पान विविधता भी है। भारत की खाद्य विविधता दुनिया के हर निवेशक के लिए एक लाभांश है। भारत के पूर्वजों ने भोजन की आदतों को आयुर्वेद से जोड़ा था। दुनिया 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रही है। बाजरा भारत के 'सुपरफूड बकेट' का हिस्सा है और सरकार ने इसकी पहचान श्री अन्न के रूप में की है। पिछले कुछ दशकों में भारत सहित कई देशों में इसे भोजन से बाहर कर दिया गया, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य, दीर्घकालिक खेती के साथ ही अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। भारत की पहल पर दुनिया में श्री अन्न को लेकर जागरुकता अभियान शुरू किया गया है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के परिणाम भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 'सूर्योदय क्षेत्र' के रूप में पहचाने जाने का एक बड़ा उदाहरण है। यह सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि-खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 'सूर्योदय क्षेत्र' के रूप में पहचाने जाने का एक बड़ा उदाहरण हैं। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्री पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री, श्री परशोत्तम रुपाला और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ-साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की विकास गाथा के तीन मुख्य स्तंभों-छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाओं का उल्लेख किया। उन्होंने छोटे किसानों की भागीदारी और मुनाफा बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किसान उत्पादन संगठनों या एफपीओ के प्रभावी उपयोग की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में 10 हजार नए एफपीओ बन रहे हैं, जिनमें से 7 हजार पहले ही बन चुके हैं। उन्होंने किसानों के लिए बढ़ती बाजार पहुंच और प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि लघु उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को संगठित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद-(ओडीओपी) जैसी योजनाएं भी छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को नई पहचान दे रही हैं।

अच्छी बात यह है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के लिए एग्री-इंफ्रा फंड के तहत हजारों परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है, जबकि मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है, जिससे निर्यातित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में कुल मिलाकर 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही कारण है कि आज भारत कृषि उपज में 50,000 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के कुल निर्यात मूल्य के साथ 7वें स्थान पर है। अतिश्योक्ति नहीं होगी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भारत ने अभूतपूर्व वृद्धि नहीं की हो।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं के बढ़ते योगदान पर प्रकाश डाला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाभ हुआ है। इस समय भारत में 9 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भोजन की विविधता और खाद्य विविधता भारतीय महिलाओं के कौशल और ज्ञान का परिणाम है। महिलाएं अचार, पापड़, चिप्स, मुरब्बा आदि कई उत्पादों का बाजार अपने घर से ही चला रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की नैसर्गिक क्षमता है। इस अवसर पर 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का उल्लेख उन्होंने किया।■

आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने का समय

ब्यूरो

अभी त्यौहार बीते हैं। त्यौहार हमें उमंग और उल्लास से ओत-प्रोत कर देते हैं। हर त्योहार को मनाने का तरीका हर किसी का अलग-अलग होता है, पर इसके साथ व्यापार एक-सा होता है। यानी खरीदारी हर कोई करता है। यदि खरीदारी देश से हो, देश के व्यापारी से हो, तो पैसा देश में ही रहेगा और भारत के छिपा हुनर का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को देश भर में काफी गति मिल रही है। इस बात से हू-ब-हू मेल खाती है प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की सोच। इसके लिए उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि त्योहारी मौके पर ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और उसके बाद उस उत्पाद या उसके निमार्ता के साथ नमो ऐप पर एक सेल्फी पोस्ट करें। अपने मित्रों और परिवार को अपने थ्रेड में शामिल होने तथा सकारात्मकता की भावना का प्रसार करने के लिए आमंत्रित करें। साथ ही यह भी कहा, 'आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथी भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें।' इसके लिए उन्होंने एक लिंक भी साझा किया, जिस पर लोग नमो ऐप पर उत्पाद या उसके निमार्ता के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि आइए इस दिवाली पर हम नमो ऐप पर 'वोकल फॉर लोकल' थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाएं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आयुर्वेद का समर्थन करना वोकल फॉर लोकल होने का एक जीवंत उदाहरण है। श्री मोदी ने उन अन्वेषकों और चिकित्सकों की सराहना भी की जो इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। जिसमें लिखा, 'धनतेरस के शुभ अवसर पर, हम आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं। यह उन अन्वेषकों और चिकित्सकों की सराहना करने का अवसर है जो इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अभूतपूर्व अनुसंधान से लेकर गतिशील स्टार्टअप तक, आयुर्वेद कल्याण के नए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आयुर्वेद का समर्थन करना वोकल फॉर लोकल होने का एक जीवंत उदाहरण भी है।'

प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की तेजी से प्रगति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' संदेश की वकालत की। यह संदेश 15 अगस्त, 2020 को लाल किले की प्राचीर से उनके लगातार सातवें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान दिया गया था। 'वोकल फॉर लोकल' का सार न केवल स्थानीय उत्पादों का उत्पादन और उपयोग करना है बल्कि उन्हें बढ़ावा देना भी है। यह पहल स्थानीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देने, क्षेत्र के भीतर बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में तैयार की गई है। ■

भारत की ताकत पर यकीन करते हैं, तो वोकल फॉर लोकल होएं। बीते त्यौहारी दिनों के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करते हुए भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का अनुरोध किया।

'वोकल फॉर लोकल' आंदोलन से कैसे जुड़ें?

लोग उत्पाद के साथ सेल्फी लेकर इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और इसे नमो ऐप पर प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें। स्थानीय सेफली थ्रेड के लिए अपने स्थानीय को तारांकित करें। एक बार जब आप इसे क्लिक करते हैं, तो आपको एक पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आप उत्पाद के साथ अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा तस्वीरें पीएम अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करेंगे।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जवानों के लिए दीवाली का उत्साह हुआ दोगुना

ब्यूरो

सच है कि उत्सवों की उमंग और उल्लास वहां होता है जहां अपने होते हैं। यह बात हर व्यक्ति स्वीकारता है और मानता है, लेकिन इसे बड़े धरातल पर सोचने, समझने और करने की असीम शक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के पास है। इसका हालिया उदाहरण है उनका हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना। सीमा की सुरक्षा के लिए त्योहार के दिन अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति कर्तव्यों के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। ये बहादुर 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। भारत सुरक्षित है क्योंकि इसकी सीमाओं की सुरक्षा हिमालय जैसी दृढ़ता रखने वाले बहादुर जवानों द्वारा की जाती है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इसके लिए आपका आभारी और ऋणी है। यही वजह है कि हर घर में बहादुरों की सुरक्षा के लिए एक दीया जलाया जाता है।

प्रधानमंत्री ने जवानों और सशस्त्र बलों की बलिदान की परंपरा को नमन किया। कहना गलत नहीं होगा कि बहादुर जवानों ने खुद को सीमा पर सबसे मजबूत दीवार के रूप में साबित किया है। राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों के योगदान पर प्रकाश डालें, तो बहादुर जवानों ने दुश्मन के जबड़े से जीत को छीनकर हमेशा नागरिकों का दिल जीता है। भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों में सशस्त्र बलों ने अनेक लोगों की जान बचाई है। बेहिचक कह सकते हैं कि सशस्त्र बलों ने भारत के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों के लिए एक स्मारक हॉल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह कदम विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने में शांति सैनिकों के योगदान को अमर बना देगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों का हर कदम इतिहास की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सशस्त्र बल इसी दृढ़ संकल्प के साथ भारत माता की सेवा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा 'आपके सहयोग से देश विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे।' पिछली दिवाली के बाद से पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों में शामिल हैं- चंद्रयान लैंडिंग, आदित्य एल1, गगनयान से जुड़े परीक्षण, स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, तुमकुर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, वाइब्रेंट विलेज अभियान और खेलों से जुड़ी उपलब्धियां। ■

हर दीवाली प्रधानमंत्री की रही यहां उपस्थिति

2014	सियाचिन, जम्मू और कश्मीर
2015	अमृतसर, पंजाब
2016	किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
2017	गुरेज, जम्मू और कश्मीर
2018	हर्षिल, उत्तराखंड
2019	राजौरी, जम्मू और कश्मीर
2020	लोंगेवाला, राजस्थान
2021	नौशेरा, जम्मू और कश्मीर
2022	कारगिल, जम्मू और कश्मीर
2023	लेप्चा, हिमाचल प्रदेश

हिमवीर शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं

हिमवीरों का त्याग, सेवा और बलिदान अनमोल है। पूरा देश इन्हें नमन करता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं। इसके लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह आगे आए। उन्होंने 10 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जवानों के लिए सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग (एसएसइबी) और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित बीओपी (बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट) पर सब्जियों, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ड्रोन का ई-लोकार्पण किया।

ब्यूरो

यदि मंशाएं सकारात्मक हों, तो नव शुरूआत के परिणाम भी सकरात्मक होते हैं। ऐसा ही 10 नवंबर को उत्तराखंड के देहरादून में देखा गया। मौका था भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का 62वें स्थापना दिवस समारोह। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने जवानों के लिए सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग (एसएसइबी) और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित बीओपी (बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट) पर सब्जियों, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ड्रोन का ई-लोकार्पण किया। यह शुरूआत वाकई खास है, क्योंकि 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये बिल्डिंग ठंडे मरूस्थल में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनेगी। क्योंकि जब यहां बाहर का तापमान शून्य से 40-45 नीचे चला जाता है और पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं हो पाता है, ऐसे में ये बिल्डिंग 18-19 डिग्री तापमान में भी जवानों को सुरक्षित रखेगी। खास है कि इस बिल्डिंग को सिर्फ 2 महीनों में ही तैयार कर लिया गया। कह सकते हैं कि ये खास बिल्डिंग देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से हिमवीरों को दीपावली की एक अनूठी भेंट है।

इसी दिन आज पहला ड्रोन 15 किलोग्राम दवाएं और सब्जियां लेकर दुर्गम इलाके में पहुंचा है, ये एक बहुत बड़ी शुरूआत है। इस पर श्री अमित शाह ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचाई पर स्थित बीओपी (बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट) पर सब्जियों, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की कल्पना प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने हम सबके सामने रखी थी। यहां शुरू हुई ड्रोन सेवा ना सिर्फ हमारे हिमवीरों बल्कि सीमावर्ती गावों की जनता के लिए भी लाभदायी सिद्ध होगी। कम लोग जानते होंगे कि दुर्गम क्षेत्र में सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए फासलों को भरना बहुत जरूरी होता है और इसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय गृह

मंत्रालय की पहल पर आईटीबीपी की 7 बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब 7 बटालियन एक साथ स्वीकृत की गई हैं, इनमें से 4 बटालियन जल्द ही तैनात हो जाएंगी। श्री शाह ने कहा कि ये 7 बटालियन और 1 सेक्टर मुख्यालय लगभग 3000 करोड़ रूपए की लागत से बनेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 147 शहीदों पर बनीं फ्लिप बुक को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी और आईटीबीपी के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आईटीबीपी को शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। भारत की 7516 किलोमीटर लंबी तटीय और 15000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा है। भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है और हिमालयी क्षेत्र में सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। बहादुर हिमवीरों ने सबसे कठिन क्षेत्रों में सीमाओं की सुरक्षा सबसे अच्छे तरीके से की है। आईटीबीपी ने 6 दशकों की अपनी अनवरत सेवा में 7 पदम श्री, 02 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 19 राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर पदक और कई अन्य पदक आईटीबीपी ने प्राप्त किए हैं, जो इस बल के शौर्य और बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे आईटीबीपी और सेना के जवान सीमा पर तैनात हैं तब तक भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अब हिम वीरांगनाएं भी देश की सीमा की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो रही हैं।

पिछले 62 वर्षों से शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ भारत की दुर्गम सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम कर रहे है हिमवीर। वाकई हिमवीरों की बहादुरी को नमन है। उनकी बहादुरी वाकई काबिलेतारीफ है। वे माइनस 45 डिग्री तापमान में देश की अग्रिम सीमा पर चौकन्ना रहकर सुरक्षा करते हैं। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। श्री शाह ने कहा कि 62 साल पहले 7 वाहिनियों के साथ शुरू हुआ आईटीबीपी आज एक लाख हिमवीरों, 60 वाहिनियों, 17 प्रशिक्षण केन्द्रों, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांड मुख्यालयों के साथ एक मजबूत बल के रूप में उभर कर आया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हिमवीरों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये सीमावर्ती गांव खाली हो जाएंगे तो इस काम में बहुत दिक्कतें आएंगी। उन्होंने कहा कि हमारे जवान जहां भी तैनात हैं, इन्हें विकास कार्यों की नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार कर सारी सुविधाएं गांव में पहुंचे, इसके लिए काम करना चाहिए। आने वाले 1 साल में 168 अनकनेक्टेड गांव सड़क, बिजली, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवाओं से भी जुड़ जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि सीमाओं पर सुविधाओं के विकास के बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भारत-चीन सीमा सुविधाओं के विकास पर 2014 से पहले औसतन प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपए खर्च होता था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में बढ़ाकर औसतन 12340 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। भारत सरकार ने सीमा पर रोड, बीओपी बनाने, जवानों को सुविधाएं देने और गांवों को सुविधायुक्त बनाने के लिए तीन गुना खर्च बढ़ाया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने इस दुर्गम क्षेत्र में 350 से ज्यादा पुल और पुलिया बनाने का काम किया है। जवानों के कल्याण के लिए सरकार ने विगत 9 सालों में कई योजनाएं बनाई हैं। खेलों के क्षेत्र में भी आईटीबीपी की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। यह भी काबिलेतारीफ है। ■

देशवासी जब दीपावली के अवसर पर अपने घर में दिया जलाते हैं, तब वे एक दिया सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों के लिए भी जलाते हैं। देश की 130 करोड़ जनता पूरे दिल से वीर जवानों के त्याग, बलिदान, साहस और शौर्य का सम्मान करती है। देश की जनता चैन की नींद सोती है क्योंकि हमारे वीर जवान अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं। श्री शाह ने कहा कि हिमवीरों का त्याग, सेवा और बलिदान अनमोल है और पूरा देश इसे नमन करता है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिमवीरों की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वायुयान और रेल में सेना की तर्ज पर देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलस बलों का भी कोटा तय कर दिया है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

वंचितों का हित है मोदी

विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर है

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के कारण देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी सोच का नतीजा है जिसकी गूंज आज देश के कोने–कोने में हो रही है। श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस, 2023 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों और वंचितों को उनके दरवाजे तक सुविधाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन–जन को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' की शुरूआत भी की।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव के साथ–साथ रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क–सह–स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की अपनी यात्रा को याद करते हुए की। उन्होंने दो साल पहले आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करने का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं और इसके गठन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विभिन्न क्षेत्रों में आज की विकास परियोजनाओं के लिए झारखंडवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड राज्य में अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत रेल मार्ग हैं।

प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव के लिए भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरक संघर्ष का जिक्र करते हुए असंख्य आदिवासी नायकों के साथ झारखंड की भूमि के जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी, सिधू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर, पीतांबर, जतरा टाना भगत और अलबर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी योद्धाओं ने देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और मानगढ़ धाम के गोविंद गुरु, मध्य प्रदेश के तांत्या भील, छत्तीसगढ़ के भीमा नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, मणिपुर के वीर गुंडाधुर, रानी गाइदिनल्यू, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने ऐसी शख्सियतों की उपेक्षा पर दुख जताते हुए अमृत महोत्सव

सरकार की प्राथमिकता

के दौरान इन नायकों को याद करने पर संतोष व्यक्त किया।

झारखंड के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने याद किया कि आयुष्मान योजना की शुरूआत झारखंड से हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज झारखंड से दो ऐतिहासिक पहल की शुरूआत हो रही है। पहली विकसित भारत संकल्प यात्रा जो सरकार और पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की पूर्णता के लक्ष्यों का एक माध्यम होगी जो विलुप्त होने वाली जनजातियों की रक्षा करेगी और उनका पोषण करेगी।

श्री मोदी ने विकसित भारत के चार 'अमृत स्तंभ' या विकसित भारत के स्तंभों अर्थात महिला शक्ति या नारी शक्ति, भारत के खाद्य उत्पादकों, देश के युवाओं और अंत में भारत के नव-मध्यम वर्ग और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में विकास की डिग्री विकास के इन स्तंभों को मजबूत करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्तमान सरकार के पिछले 9 वर्षों में चार स्तंभों को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों और कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार पीएम जनमन या पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया और एक अलग बजट आवंटित किया। उन्होंने बताया कि आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन के तहत सरकार आदिवासी समूहों और आदिम जनजातियों तक पहुंचेगी, जिनमें से अधिकांश अभी भी जंगलों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाखों की आबादी वाले 75 ऐसे आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों की पहचान की है जो देश के 22 हजार से अधिक गांवों में रहते हैं। ■

विकसित भारत संकल्प यात्रा

प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को पूर्णता प्रदान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। योजनाओं की संतृप्ति के इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़े कदम में, प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' शुरू की। यात्रा का लक्ष्य लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगा। यात्रा के दौरान तैयार किए गए विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के शुभारंभ के अवसर पर झारखंड के खूंटी में आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को हरी झंडी दिखाई। यात्रा शुरूआत में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी, 2024 तक देश भर के सभी जिलों को कवर करेगी।

अब कम होंगे सरकार में लंबित मामले

सरकार में लंबित मामले का निपटारा करेगा अभियान 3.0। यह अभियान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने किया। हर्ष का विषय है कि गृह मंत्रालय ने सभी लक्ष्यों को लगभग शत-प्रतिशत हासिल किया।

ब्यूरो

काम करने का जज्बा हो तो मार्ग में आई तकलीफें मुश्किल जरूर देती हैं, लेकिन समझदार लोग बेपरवाह होकर पार करते हुए मंजिल को पाने में जुट जाते हैं। कुछ ऐसा ही है अभियान 3.0। अभियान 3.0 के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की स्वच्छता को संस्थागत बनाने एवं सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरणा लेते हुए और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय ने सफलतापूर्वक विशेष अभियान 3.0 का संचालन किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित किया गया था और इसमें लंबित मामलों के निपटान, स्थान के बेहतर प्रबंधन और स्थायी पर्यावरण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभियान कई मायनों में खास रहा। मसलन पैनी निगरानी। यही वजह बनी इसकी सफलता की।

इस अभियान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री और गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रगति की नियमित निगरानी की गई। दैनिक प्रगति की निगरानी एक समर्पित टीम ने की तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने होस्ट किए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर इसे अपलोड किया। सच है कि कोई अभियान सफल तब होता जब उसकी पल-पल की प्रगति की पैनी निगरानी रखी जाए। गृह मंत्रालय ने सभी लक्ष्यों को लगभग शत-प्रतिशत हासिल किया। लगभग 167240 वर्ग फुट स्थान खाली किया गया और 95000 से अधिक फाइलों को हटाया गया। स्क्रैप निपटारे से ₹5.82 करोड़ की आमदनी हुई। गृह मंत्रालय के सभी स्थानों पर 10,274 अभियान चलाए गए।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय अभियान में उत्साह से भाग लिया तथा इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि सफाई, लंबित मामलों के निपटान आदि लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से एक प्रारंभिक चरण के साथ अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान, कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। ■

संकल्प से सिद्धि की सोच को जन-जन तक पहुंचा रहे गृह राज्यमंत्री

ब्यूरो

सरकार की योजनाओं को समाज के लोगों के हितों के लिए लागू करना सरकार की कोशिश रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार ऐसे कामों को कर रहा है। देश के तीनों केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अपने दायित्वों के निर्वहन में लगे हुए हैं। संकल्प से सिद्धि की सोच को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। असल में, भीड़ से हटकर जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनके कामों की चर्चा हर ओर होती है। वे समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुख्यालय में 6 और 7 नवंबर को फिंगर प्रिंट ब्यूरो के निदेशकों के 24वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने एआईबीई 2022 के रैंक धारकों को पुरस्कार भी दिए। दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो के निदेशक और राज्यों के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। श्री अजय मिश्रा ने जांच में सहायता के लिए विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों को विकसित करने और तैनात करने में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता पर बल दिया।

देश के युवाओं में उत्साह और अतीत के गौरव को याद दिलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन पांच नवंबर को पटना में किया गया। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय वेटनरी कॉलेज मैदान में श्री राम कर्मभूमि न्यास एवं मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा देश के वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित 'मेरे देश की धरती-एक दीप राष्ट्र के नाम' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्वनी चौबे की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 11.11 लाख दीप जलाकर शहीदों को भी नमन किया गया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक ने सीमा सुरक्षा बल के पर्वतारोहण अभियान दल को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा दो नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लू पर चढ़ने वाले पर्वतारोहण अभियान दल के सदस्यों से बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गर्व की बात यह है कि पर्वतारोहण अभियान दल में 2 महिला कर्मी भी शामिल थीं।

उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल की 18 सदस्यीय टीम नेपाल में दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनास्लू पर चढ़ाई करने के लिए

नई दिल्ली से 12 सितंबर को रवाना हुई थी। यह टीम 15 बेहद अनुभवी पर्वतारोहियों का एक मिश्रण थी, जिनके नाम कई सफल आरोहण हैं। इस टीम का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तू ने किया था। सीमा सुरक्षा बल के इतिहास में पहली बार, दो महिलाकर्मी भी इस अभियान के साथ 8,163 मीटर ऊंची चोटी पर अपना झंडा गाड़ आईं। ■

तटीय पुलिसिंग के लिए सरकार का एकीकृत दृष्टिकोण

वाइस एडमिरल (रि)
जी अशोक कुमार

भारत का समुद्र तट 11,000 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें 1389 द्वीप शामिल हैं। यहां पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसका मूल्य ₹75 लाख करोड़ से अधिक है और इसमें ₹63 हजार करोड़ से अधिक का मत्स्य निर्यात शामिल है। भारतीय सागरीय सुरक्षा के साथ ही तटीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक जुड़ा है। इससे देश की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा दोनों ही सीधे रूप से जुड़ी हुई हैं।

तटीय सुरक्षा पूरी समुद्री सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। समुद्र तट जहां एक ओर बाहरी खतरों के खिलाफ ढाल का काम करती है, वहीं दूसरी ओर समस्त दुनिया का प्रवेश द्वार भी है। भारत में 2008 में मुंबई में हमले हुए। इसके लिए आतंकवादियों ने पाकिस्तान से तटीय मार्ग से ही प्रवेश किया था। इस घटना ने मौजूदा तटीय सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया और तटीय सुरक्षा में रणनीतिक बदलाव को प्रेरित किया।

समुद्री सुरक्षा पर स्पष्ट ध्यान देने और इसके बहु-राष्ट्रीय और बहु-एजेंसी चरित्र दोनों को पहचानने के साथ, वर्तमान सरकार द्वारा दो प्रमुख कदम उठाए गए हैं। पहला, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) का दृष्टिकोण है, जिसके तहत हमारी समुद्री सुरक्षा सहयोग पहल आगे बढ़ती है। दूसरा था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एनएमएससी) की नियुक्ति। इसके साथ ही, प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तटीय सुरक्षा के लिए पूर्ववर्ती नोडल अधिकारियों को राज्य समुद्री सुरक्षा समन्वयक (एसएमएससी) के रूप में फिर से नामित किया गया है।

तटीय पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें ली गई हैं। 2016 में सरकार ने प्रत्येक तटीय राज्य में समुद्री अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक तटीय पुलिस स्टेशन की स्थापना की। यह एक बड़ा कदम था जो समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है। दिसंबर 2019 में, सरकार ने सभी केंद्रीय अधिनियमों के तहत तटरक्षक बल को कानूनी रूप से सशक्त बनाया, जो अब समुद्री अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। इसके अलावा गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना भी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तटीय क्षेत्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और विकास प्रदान करता है। ये सभी पहलें तटीय सुरक्षा में सुधार लाने और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा में मदद करने के लिए क्रियाशील रूप से योगदान कर रही हैं।

समुद्री डोमेन जागरूकता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन में मदद करती है। अक्टूबर 2022 में, सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (एनएमडीए) परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना में एक डिजिटल तटीय सुरक्षा मानचित्र शामिल होगा और ऐप-आधारित भू-बाड़ वाली तस्वीरें सभी को प्रदान की जाएगी। यह पहल तटीय पुलिस स्टेशनों और समुद्री सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

तटीय पुलिसिंग की संशोधित रणनीति में समुदायों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण तत्व माना जा रहा है। मछुआरों और तटीय समुदायों को शामिल करने से सामुदायिक सहभागिता पहलों में सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने में मदद करती है। संचार ट्रांसपोंडर के चालू होने से मछुआरों को मछली पकड़ने के क्षेत्र और मौसम की चेतावनियाँ प्राप्त होती हैं। यह जानकारी उनकी सुरक्षा, तकनीकी अद्यतन और समुद्री संवर्धन में मदद करती है। इसी तरह से, एमडीए इस प्रकार की संचार और जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है, जिससे समुद्री सुरक्षा में और भी मदद मिले।

तटीय पुलिसिंग के एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ, 2007 में जारी तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा संशोधित किया गया है। इसमें सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनएमएससी के सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं। यह संशोधन व्यापक है और जल्द ही जारी किया जाने वाला है।

भारतीय समुद्री सुरक्षा की रणनीति में कई उपायों ने सुरक्षा को मजबूती और प्रभावी बनाया है। यह रणनीति समुद्री खतरों के खिलाफ जवाब देने में सक्षम होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के कल्याण और सुरक्षा को भी महत्त्व देती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 'सुदर्शन चक्र' के रूप में भारत की तटीय सुरक्षा रणनीति को प्रस्तुत किया है। यह चक्र उस दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है जो देश की समुद्री सुरक्षा को बहुस्तरीय रूप से प्रबंधित करता है। इससे तटीय सुरक्षा परिचालन में दक्षता का संरक्षण होता है। इस प्रकार की रणनीति में सामुदायिक सहभागिता, नवीनतम तकनीक, सुरक्षा प्रणालियों का अनुसरण, और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम शामिल होते हैं। यह समुद्री सुरक्षा में निरंतर सुधार और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। ■

(लेखक भारत सरकार के समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं।)

8 नवंबर, 2023 को आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने एनसीओएल लोगो, वेबसाइट और ब्रॉशरका शुभारंभ और एनसीओएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

भारतीय सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के बीच तीन दिवसीय 7वीं वार्षिक समन्वय बैठक 6 नवंबर को शुरू हुई। दोनों पक्षों ने सर्वसम्मति से दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपायों को लागू करने का संकल्प लिया।

8 नवंबर को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ब्यूरो के महानिदेशक, श्री बालाजी श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक, श्री अमित गर्ग को नव प्रस्तावित ट्रॉफी 'Bureau of Police Research and Development Trophy for Innovation in Policing' प्रदान की, जिसे एनपीए में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट स्क्वाड प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा।

क्या आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं? अपने पैसे गवां चुके हैं? ऐसे में घबराएं नहीं और कॉल करें 1930 हेल्पलाइन पर। 24 घंटे के भीतर CYBERCRIME.GOV.IN पर फ्रॉड विवरण सबमिट करें। आप जितनी जल्दी 1930 हेल्पलाइन शिकायत करेंगे, आपके पैसे मिलने की संभावना उतनी ही मजबूत होगी। यह वीडियो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के यू ट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' के अंतर्गत साझा किया गया है।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

आज, तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले प्रत्येक परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है। 2014 के बाद मत्स्य उत्पादन में 80 प्रतिशत और निर्यात में 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सागरमाला योजना तटवर्ती क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि तटीय इलाकों में नए व्यापार और उद्योगों का विस्तार हो सके।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India https://bprd.nic.in